मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) एन०सी०ई०आर०टी० ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 1989-90 से आज की तिथि तक 11,78,540.00 रुपये की कीमत के 21 कम्प्यूटर खरीदे।

(ग) एन०सी०ई०आर०टी० एक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान है। शोध और शिक्षक प्रशिक्षकों और शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए कम्प्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान शिक्षक प्रशिक्षण देने वालों और शिक्षकों के लिए 62 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। स्कूल छात्रों के लिए यह किसी शैक्षिक पाठ्यक्रम को पेशकश नहीं करती।

Training Vocational courses in Navo-daya Vidyalayas

2569. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to refer to the answer to U.Q. No. 624 given in the Rajya Sabha on 28th Feb., 1992 and state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to establish one Navodaya Vdyalaya in each district of the country;

(b) if so, by when this decision is likely to be imp. emented; and

(c) whether Government propose to introduce training vocational courses to be taken up in Navodaya Vidyalayas?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) and (b) Yes, Sir. The present objective of the Government is to open Navodaya Vid yalayas in all the Districts of the country, if possible during the next three years, depending upon the suitability of the proposals received from the StatelUT Governments concerned, availability of physical facilities and financial resources.

(c) Yes, Sir. Vocational courses have already been started in 16 Navo-daya Vidyalayas at —2 stage from the current academic year.

ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए शिक्षा

2570. श्री अजीत जोगी :
कुमारी आलिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं ;

(ख) बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में महिलाओं का शिक्षा-स्तर क्या है ;

(ग) विशेष रूप से पिछड़े राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं में शिक्षा और साक्षरता के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 'साक्षरता मिशन' तथा अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत कौन-कौन से नए कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों के मिलने में असमानता को, महिलाओं को अधिकार देकर, प्रारम्भिक शिक्षा के लिए उनका दाखिला और उनकी शिक्षा जारी रखवाकर, और अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से, दूर करने पर बल दिया गया है।

(ख) 1991 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष और इससे अधिक आयु की जनसंख्या की महिला साक्षरता दर की राज्यवार स्थिति विवरण में दी गयी है।

(ग) सारे देश में महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाओं की पहल की गई है जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया गया है । इनमें कुछ नीचे दी गई है :

(i) **महिला समाख्या** : इस कार्यक्रम में ऐसी क्रियाविधि तैयार करने पर बल दिया गया है जिससे महिलाओं को अपनी शिक्षा की स्वयं योजना बनाने और उसका अनुश्रवण करने का अवसर मिल सके और वे नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकें । इसका उद्देश्य है—ग्रामीण स्तर पर शैक्षिक योजनाएं तैयार करने में महिलाओं को शामिल करना और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों, ग्रामीण स्कूल शिक्षकों का प्रशिक्षण और शैक्षिक सामग्री तैयार करने जैसे शैक्षिक निवेश प्रदान करना है । यह योजना 10 जिलों में शुरू की गई है । उनमें से 3–3 जिले गुजरात और कर्नाटक के हैं और 4 जिले उ० प्र० के हैं ।

(ii) **स्कूल शिक्षा** : स्कूल शिक्षा में लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदमों में, स्कूलों में और अधिक महिला शिक्षकों की भर्ती, प्राथमिक स्कूलों में कम से कम एक महिला शिक्षक की नियुक्ति आपरेशन ब्लैक-बोर्ड, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और वर्दियां वितरित करने, लड़कियों को सभी सरकारी, स्थानीय निकाय और सहायता प्राप्त स्कूलों, में कक्षा VIII तक और अधिकांश राज्य/संघ-शासित क्षेत्रों में कक्षा X तक निःशुल्क शिक्षा जैसी प्रेरणादायक योजनाएं शामिल हैं ।

(iii) **अनौपचारिक शिक्षा** : शैक्षिक रूप से पिछड़े 10 राज्यों में लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए नब्बे प्रतिशत सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की जाती है और शेष 10% व्यय सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

(iv) **प्रौढ़ शिक्षा** : प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के विषय में जानकारी उत्तर के भाग (घ) में दी गई है ।

(घ) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य वर्ष 1995 तक 15–35 आयु वर्ग में 80 मिलियन प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यसाधक साक्षरता प्रदान करना है । रा०सा०मि० का मुख्य बल ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर महिलाओं और अनु०जातियों/अनु० जनजातियों पर है । प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए उठाए गए विशिष्ट कदम इस प्रकार हैं :—

- साक्षरता के लिए महिला स्वयंसेविकाओं निरक्षरों को जुटाने के लिए माहौल के लिए किए जाने वाले प्रयास ।

- पठन/पाठन सामग्री, प्रशिक्षण आदि के पाठ्यक्रम सामग्री और पाठ्यचर्या में शिक्षा द्वारा महिला समानता और अधिकार प्रदान करना, संदेश शामिल करना ।

- विशेष रूप से महिलाओं के लिए कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों को बड़ी संख्या साक्षरता कार्य में संलग्न करना ।

- श्रमिक विद्यापीठों द्वारा महिला कार्यकर्मियों पर विशेष ध्यान ।

- साक्षरता कौशलों के अवरोधन तथा उनके जीवन दशाओं को ऊपर उठाने में इन कौशलों के प्रयोग के लिए सतत-शिक्षा के माध्यम से अवसरों का प्रावधान

- महिला साक्षरता तथा उन्हें अधिकार प्रदान करने के संबंध में फिल्में बनाना दूरदर्शन के माध्यम से प्रेरक और शैक्षिक प्रयोजन से इनका प्रसारण ।

पूर्ण साक्षरता अभियान में अधिकांश लाभार्थी महिलायें हैं ।

विवरण

7 वर्ष और उससे ऊपर की आयु की जनसंख्या की महिला साक्षरता दर

क्र०सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	महिला साक्षरता दर
1.	आन्ध्र प्रदेश	33.71
2.	अरूणाचल प्रदेश	29.37
3.	आसाम	43.70
4.	बिहार	23.10
5.	गोवा	68.20
6.	गुजरात	48.50
7.	हरियाणा	40.94
8.	हिमाचल प्रदेश	52.46
9.	जम्मू और कश्मीर	26.15*
10.	कर्नाटक	44.34
11.	केरल	86.93
12.	मध्य प्रदेश	28.39
13.	महाराष्ट्र	50.51
14.	मणिपुर	48.64
15.	मेघालय	44.78
16.	मिजोरम	78.09
17.	नागालैण्ड	55.72
18.	उड़ीसा	34.40
19.	पंजाब	49.72
20.	राजस्थान	20.84
21.	सिक्किम	47.23
22.	तमिलनाडु	52.29
23.	त्रिपुरा	50.01
24.	उत्तर प्रदेश	26.02
		47.15

संघशासित क्षेत्र	
1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	66.22
2. चंडीगढ़	73.61
3. दादरा और नागर हवेली	26.10
4. दमन और दीव	61.38
5. दिल्ली	68.01
6. लक्षद्वीप	70.88
7. पांडिचेरी	65.79
भारत	39.42

*अतिरिक्त बहिर्वेशन से अंकलित अनुमान

नई शिक्षा नीति में राष्ट्रीय एकता

2571. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई शिक्षा निति तैयार करते समय देश में युवा वर्ग के विकास के लिए राष्ट्रीय एकता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है ;

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि नई नीति में भारतीय इतिहास और संस्कृति को सही-सही प्रतिबिम्बित किया जाए, सरकार ने उपयुक्त कदम उठाए हैं ;

(ग) क्या छात्रों में एकता की भावना उत्पन्न करने के लिए विद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकों में उपयुक्त संशोधन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) जी, हां ।

(घ) विवरण संलग्न है ।